

हाईकोर्ट ने वो कर दिखाया जो सरकार नहीं कर पाई : एस.आई. भर्ती परीक्षा-2021 रद्द की

हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि एस.आई. भर्ती परीक्षा 2021 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार ही पुनः आयोजित की जाए

- यादवेन्द्र शर्मा -

जयपुर, 28 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यापक पेपर लीक और नकलबाजी के आरोपों को सही मानते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग (आर.पी.एस.सी.) द्वारा एस.आई. भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द कर, महाधिवक्ता की राय के अनुसार 2021 की विज्ञप्ति में संशोधन कर पुनः आयोजित करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार जुलाई 2025 में जारी नई विज्ञप्ति में भी संशोधन कर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर 2021 की भर्तियों को भरने का प्रावधान कर सकती है।

हाईकोर्ट के आदेशानुसार पुनः आयोजित परीक्षा में सभी उम्मीदवारों को आयु सम्बन्धी योग्यता में रियायत दी जाए, साथ ही सभी योग्य अभ्यर्थियों को 2021 में मिल रहे आरक्षण व अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा

■ हाईकोर्ट के आदेशानुसार पुनः आयोजित परीक्षा में सभी उम्मीदवारों को आयु सम्बन्धी योग्यता में रियायत दी जाए, साथ ही सभी योग्य अभ्यर्थियों को 2021 में मिल रहे आरक्षणों व अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जाए।

■ अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व की सरकारी सेवा को छोड़ा था और फिर एस.आई. भर्ती परीक्षा में चयनित हुए थे।

■ न्यायाधीश समीर जैन ने अपने आदेश में तत्कालीन आर.पी.एस.सी. अध्यक्ष संजय श्रोतिया समेत अन्य सदस्य, जिनमें बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका, मंजू शर्मा, संगीता आर्या और जसवंत राठी पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इन अफसरों ने व्यापक पेपर लीक को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई और आर.पी.एस.सी. की विश्वसनीयता को छलनी किया।

है कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व की सरकारी सेवा का छोड़ा था और फिर एस.आई. भर्ती परीक्षा में चयनित हुए

2025 तक योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए जाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश से वो कर दिखाया है जो पिछले डेढ़ वर्ष से राज्य सरकार करने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि, जैसा कि विदित है कि इस मामले में राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एस.ओ.जी.) ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, वी.के. सिंह, की देखरेख में विस्तृत जांच कर रिपोर्ट दायर करी थी कि एस.आई. भर्ती-2021 में अपराधिक गिरोह शामिल थे, जिन्होंने आर.पी.एस.सी. के अध्यक्ष सहित छह सदस्यों के साथ मिलकर व्यापक पेपर लीक के षड्यंत्र को अंजाम दिया था और फिर चयनित अभ्यर्थियों से 'इंटरव्यू' में घूस के लिए अच्छे अंक देने का भी षड्यंत्र रचा था।

बताया जा रहा है कि इस मामले की शुरूआती जांच के दौरान स्वयं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिनेश पटनायक कैनडा में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त

नयी दिल्ली, 28 अगस्त। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी दिनेश के. पटनायक को कैनडा में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि उनके शीघ्र ही पद भार ग्रहण करने की संभावना है।

पटनायक भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं और वह स्पेन में भारत के राजदूत की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

उल्लेखनीय है कि कैनडा में भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री

■ दो वर्ष पहले टूटो के शासनकाल में दोनों देशों में भारी तनाव के कारण कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर दिए गए थे।

नरेन्द्र मोदी और कैनडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच गत जून में जी-7 की आउटरीच बैठक के दौरान हुई मुलाकात में संबंधों को सुधारने पर बनी सहमति के बाद की गयी है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने दिल्ली और ओटावा में उच्चायुक्तों की बहाली का निर्णय लिया था।

खालिस्तानी संगठन से जुड़े हरदीप सिंह निज्जर की दो वर्ष पहले हुई हत्या को लेकर जस्टिन टूडो सरकार ने इसमें भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। भारत ने इससे साफ इंकार किया था (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘मैंने कभी नहीं कहा मैं 75 साल में रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को हो जाना चाहिए’

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल की आयु में रिटायर होने के विवाद पर यह टिप्पणी की

- संघ प्रमुख भागवत के इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में देखा जा रहा है।
- ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितम्बर को और मोहन भागवत 11 सितम्बर को 75 साल के हो रहे हैं।
- संघ प्रमुख ने आरएसएस के शताब्दी वर्ष के सम्बंध में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह भी कहा कि भाजपा व आरएसएस के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं है। हमें एक-दूसरे पर विश्वास है।

जोती है, हम चाहें या न चाहें। अगर मैं 80 साल का हूं और संघ कहता है कि जाओ और शाखा चलाओ, तो मुझे करना ही होगा। संघ जो भी कहता है, हम करते हैं। यह किसी की सेवानिवृत्ति के लिए नहीं है। हम सेवानिवृत्त होने या काम करने के लिए तैयार हैं। जब तक संघ चाहता है।

उन्होंने कहा कि मैं शाखा चलाने में माहिर हूं, भाजपा सरकार चलाने में माहिर है, हम एक-दूसरे को सिर्फ

सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम फैसला नहीं करते, अगर हमें फैसला करना होता तो क्या इसमें इतना समय लगता।

भाजपा और आरएसएस के बीच मतभेद के सवाल पर संघ प्रमुख ने कहा कि मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते। हमारे यहां मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे पर विश्वास है...क्या भाजपा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘प्र.मंत्री मोदी की सतही विदेश नीति का देश को नुकसान ही हुआ’

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोप लगाया कि, सरकार की मुस्कान, गले मिलने और “सेल्फी” लेने पर आधारित विदेश नीति, देश के हितों की सुरक्षा नहीं कर सकी

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 अगस्त। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि सरकार देश की रक्षा करने में विफल रही है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जी.टी.आर.आई.) की रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग एक प्रतिशत जीडीपी पर असर पड़ सकता है और इसका फायदा चीन को मिलेगा।

बुधवार से अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त शुल्क लागू होने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यापार समझौता न कर पाने और देश की रक्षा न कर पाने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने चेतावनी दी कि टैरिफ की पहली मार में कम से कम 10 सैक्टरों को 2.17 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि विदेश नीति के दिखावटी कार्यक्रम, मुस्कानें, गले लगाना और सेल्फी, ने राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाया है। खड़गे ने कहा, “आपके प्यारे दोस्त

■ खड़गे ने इसी संदर्भ में यह भी कहा, कि “ट्रेड डील” (व्यापारिक समझौता) नहीं होने से 10 सैक्टरों में ही 2.17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा।

■ भारत के “टैक्सटाइल उद्योग” में ही 5,00,000 नौकरियां खत्म हो जायेंगी। जैम्स व ज्वेलरी क्षेत्र में 1,50,000 से 2,00,000 नौकरियां कम हो जायेंगी, हीरे की कटिंग व पॉलिशिंग उद्योग में भी एक लाख वर्कर बेरोजगार हो जायेंगे।

“अबकी बार, ट्रंप सरकार” ने आज से भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। हमारे किसान, खासकर कपास के किसान, बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आपने कहा था कि आप उनकी रक्षा करने के लिए कोई भी “निजी कीमत” चुकाने को तैयार हैं, लेकिन आपने उनके नुकसान को कम करने और आजीविका बचाने के लिए कुछ नहीं किया।”

उन्होंने कहा कि कई निर्यात-आधारित अहम सेक्टर, खासकर एमएसएमई, में बड़े पैमाने पर नौकरियों का नुकसान होगा।

खड़गे ने कहा कि “भारतीय वस्त्र निर्यात क्षेत्र में लगभग 5 लाख नौकरियों का नुकसान हो सकता है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल है।”

उन्होंने बताया कि अगर शुल्क जारी रहा तो रत्न और आभूषण सेक्टर में भी 1,50,000 से 2,00,000 नौकरियों पर खतरा है। उन्होंने कहा, सौदाक्षेत्र में हारे काटने और पॉलिश करने वाले करीब 1,00,000 मजदूरों की नौकरियां अप्रैल से ही जा चुकी हैं, जब अमेरिका ने 10 प्रतिशत बेस टैरिफ लगाया था।

उभरे हैं, जबकि पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची सबसे निचले स्थान पर हैं। गुरुवार को जारी राष्ट्रव्यापी सूचकांक में, 31 शहरों की 12,770 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट व महिला सुरक्षा सूचकांक 2025, के अनुसार जयपुर के साथ दिल्ली, पटना व कोलकाता महिलाओं के लिए सर्वाधिक असुरक्षित शहर हैं, वहीं, मुम्बई, कोहिमा, इटानगर आइजोल और भुवनेश्वर सर्वाधिक सुरक्षित माने गए हैं।

भारत ने ट्रंप की “टैरिफ दादागिरी” के जवाब में गिड़गिड़ाने की नहीं सामना करने की नीति फाइनल की

इस नीति के तहत भारत कोई अर्जी नहीं देगा कुछ रियायत करने की, और न ही इन्तज़ार करेगा ट्रंप में हृदय परिवर्तन होने का

■ भारत के नीतिकारों का मानना है, “डॉमैस्टिक कंज़ंप्शन” (देश की घरेलू डिमान्ड) का आज भी योगदान, जी.डी.पी. के आंकड़े में 61 प्रतिशत है, और कुछ और टैक्स आदि की रियायतें देकर भारत की “घरेलू डिमान्ड”, को और अधिक बढ़ाने की काफी गुंजाइश (स्कोप) है।

■ इसी दिशा में बढ़ते हुए, हाल ही में जी.एस.टी. का सरलीकरण करने की घोषणा की गई है, तथा दो ही “स्लैब” (वर्ग), 12 प्रतिशत व 18 प्रतिशत रह जायेंगे।

■ भारत का यह इतिहास रहा है कि जब भी विदेशी दबाव पड़ा है, भारत दबाव के आगे झुका नहीं। पं. नेहरू पर भारी दबाव था शीत युद्ध के जमाने में, अमेरिका का खेमा या रूस का खेमा जॉइन करने का, पर, उन्होंने “नॉन एलाइन्ड” (निर्मुक्त) रहने का निर्णय लिया। इंदिरा गांधी भी, 1971 के संकट के समय अमेरिका के दबाव में कतई नहीं आईं तथा 1998 में एन.डी.ए. की सरकार ने “न्यूतिलियर टेस्ट” करने का फैसला किया, पाश्चात्य देशों द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद।

■ अमेरिका क्यों हाथ धोकर भारत के पीछे पड़ा है इस पर एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा, रूस से तेल खरीदने का मुद्दा तो बहाना मात्र है असली कारण अर्थव्यवस्था है। अमेरिका भारत के कृषि बाजार में घुसना चाहता है, और भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि यह देश के किसानों के लिए घातक होगा।

■ वाइट हाउस के ट्रेंज़री सैक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट ने भी इस बात की पुष्टि यह कहकर कर दी, कि विवाद सिर्फ “रूसी तेल” के कारण नहीं है। वॉशिंगटन की टैरिफ रण का निशाना तो भारत की “ट्रेड” सम्बंधी बाधाएं हैं।

संघर्ष विराम लागू करने के बार-बार किए जा रहे दावों तक।

अनुभवों विदेश नीति विश्लेषकों का मानना है कि मोदी की अत्यधिक व्यक्तिगत विदेश नीति शैली और विश्व

नेताओं से हरेक से एक निजी संबंध बनाने की उनकी इच्छा ने भारत-अमेरिका संबंधों में मौजूदा संकट को जन्म दिया है। एक पूर्व राजनयिक ने बताया कि मोदी और भाजपा इस

विश्वास में थे कि अमेरिका भारत की प्रगति की कुंजी है, और इसलिए वॉशिंगटन के साथ रिश्तों पर ही सारा ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन जब सारे उम्मीदें एक पर ही टिका दी जाए, तो खतरा बढ़ जाता है।

ब्लूमबर्ग को बुधवार को दिए इंटरव्यू में नवरो ने कहा, “भारत जो कर रहा है, उससे अमेरिका में हर कोई हार रहा है। उपभोक्ता, व्यवसाय, सब को नुकसान हो रहा है। नौकरियां जा रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आमदनी और मजदूरी पर असर पड़ रहा है। और फिर टैक्स देने वालों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें मोदी की जंग के लिए फंड देना पड़ रहा है।”जब उनसे पूछा गया कि क्या वे “पुतिन की जंग” कह रहे हैं, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बाढ़

सुकमा, 28 अगस्त । छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में लगातार बारिश से उफान पर आई शबरी नदी और नालों के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर गौदम नाला के पास 48 घंटे से फंसी बस में सवार यात्रियों को जिला प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की

■ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 48 घंटे से फंसी बस के यात्रियों को बचाया गया। अब तक 2000 नागरिकों का पुनर्वास किया जा चुका है।

टीमों ने नाव की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। इसके साथ ही यात्रियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था भी 6 की गई।

जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज़ कर दिए हैं। अब तक जिले के विभिन्न प्रभावित इलाकों में 22 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहाँ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

केवल आत्मज्ञान ही हृदयात्मा को सच्चा आनंद प्रदान करता है। –रामतीर्थ

चुनाव के हेतु मतदाता सूची चुनाव आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में संविधान के अनुच्छेद 324, 325, 326, 327 व 328 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बनाई जाती है

सटीक मतदाता सूची, लोकतंत्र का प्राण है। मतदाता सूचियों की शुचित्ता की पूर्ण जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। समय–2 पर मतदाता सूचियों का परीक्षण भी आवश्यक प्रतिक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा पिछली मतदाता सूची की तुलना में पाई जाने वाली विसंगतियों और बदलाव को चिन्हित किया जाएगा, मतदाता सूचियों को शुद्ध किया जाता है। बिहार में इस समय वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा का कार्य SIR (एसआईआर) चल रहा है। बिहार में 1.56 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेन्ट नियुक्त किये गये हैं। सभी दलों ने अपने अपने एजेन्ट नियुक्त किये हैं। वार्ड के निवासी वांछित जानकारी उपलब्ध कराते हैं। फार्मसु को अपलोड किया जाता है। आपत्तियां ली जाती हैं। सुनवाई की जाती है। विशेष गठित टीम सुपरवाइज करती है। प्राप्त डोक्यूमेन्ट्स का परीक्षण होता है। अपील का भी प्रावधान है।

संविधान में अनुच्छेद 324 के द्वारा निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के पूर्ण अधिकार चुनाव आयोग को दिये हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है यह देश की एक मात्र संवैधानिक संस्था है जिसे निर्वाचन के सम्बन्ध में कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधान निर्मात्री के अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 325 में इस संस्था को मतदाता सूची बनाने का अधिकार है, पात्र व्यक्ति को सूची में शामिल करने का अधिकार है। अनुच्छेद 326 स्पष्ट निर्देश देता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसे वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव में मतदान का अधिकार होगा। अनुच्छेद 327 में यह निर्देश है कि इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुये समय–2 पर विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन, राज्य के विधान मंडल तथा विधान मंडल के सदस्यों के लिये निर्वाचन (मतदान) सूची तैयार करना आदि सभी विषय हैं, उपबन्ध कर सकेगी। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन सम्बन्धित मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव आयोग की शक्तियों के अधीन संसद का कानून है।

संविधान की उपरोक्त समीक्षा के अनुसार यह स्पष्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 324, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 कानूनी और संवैधानिक बाध्यातयें निश्चित करते हैं और मतदाता सूचियों के मामलों में चुनाव आयोग को पूर्ण अधिकार है, यहां तक संविधान को न्यायालय का कोई दखल भी स्वीकार नहीं है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि परम शक्ति प्राप्त देश का चुनाव आयोग है और देश का नागरिक ही केवल मतदान करने का अधिकारी है।

बिहार में SIR (एसआईआर) को लेकर मतदाता सूचियों में कई विसंगतियों को चिन्हित करते हुये प्रश्न उठाये हैं और ड्राफ्ट मतदाता सूची को चुनौती है। सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 65 लाख मतदाताओं की लिस्ट जारी की गई है, उनके नाम प्रकाशित किये हैं जो अब पुनः फार्म भरकर देंगे और चुनाव आयोग के अधिकारी उन पर विचार कर अपना निर्णय देंगे कि कितने नाम मतदाता सूची में जोड़े जावेंगे और कितनों के नाम काटे जावेंगे। अभी तक 12 राजनीतिक पार्टियों में से एक ने 12 आपत्तियां पेश की हैं। दिनांक 8 सितम्बर को पुनः सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी।

विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में मतदाता सूचियों की विसंगतियों को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग, केन्द्र सरकार के इशारे पर कार्य कर रहा है और वह गलत रूप से मतदाताओं के नामों को काट रहा है और उसका यह कार्य वोट चोरी कहा जा रहा है। वोट चोरी के आरोप संसद में, संसद के बाहर और सड़कों पर तथा अब तो यात्रा के आयोजनों में लगाये जा रहे हैं। विपक्ष के सभी नेता, जो राहुल गांधी के साथ में अपने को बता रहे हैं वे भी केन्द्र सरकार व चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने के गम्भीर आरोप लगा रहे हैं। देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। नारों में शालीनता व सभ्यता कहीं खो गई है। चुनाव आयोग को कटघड़े में खड़ा किया गया है। विपक्ष संवैधानिक संस्था को सम्मान देना भूल गया है वह भूल गया है कि संविधान के अनुच्छेद

वस्तुतः विपक्ष नेता राहुल गांधी का केस है कि केन्द्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों में गडबडी की है, सही मतदाताओं के नाम काटे हैं जीवित व्यक्तियों को मृतक बना दिया है। दो-दो स्थानों पर नाम दर्ज किये हैं आदि। इस कार्यवाही को वे वोटों की चोरी की संज्ञा दे रहे हैं, जबकि यह केस चोरी का नहीं है। उन्होंने इस हेराफेरी का न तो कोई सबूत दिया और न कोई शहादत दी जिससे वे आरोपों को साबित कर सकें।

वे महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि अन्य राज्यों में पहले हो चुके चुनावों के बाबत भी हैं। यह भी उल्लेखनीय है और प्रासांगिक भी राहुल गांधी इन्में से किसी राज्य के मतदाता नहीं हैं।

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से जो शपथ पत्र सबूतों सहित पेश करने को कहा है उसका आधार मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 का नियम 20(3)(बी) है। जिसमें उल्लेख है कि जो व्यक्ति चुनाव राज्य की मतदाता सूची में मतदाता पंजीकृत नहीं है, यदि वह व्यक्ति चुनाव की मतदाता सूची की वैधता को विसंगतियों के आधार पर चुनौती देता है तो उसे शपथ पत्र सबूतों के साथ देना चाहिये। नोटिस की अवधि समाप्त हो चुकी है, किन्तु अभी तक राहुल गांधी ने कोई उत्तर नहीं दिया है, उनमें यह व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति (नोटिस देने वाला) उत्तर नहीं देता है तो यह माना जावेगा कि उसके आरोप गलत हैं।

पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उक्त नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति यदि विसंगतियों पर झूठे आरोपों का प्रचार करता है और मतदाताओं की भावनाओं को भडकाता है तो उसे 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

संविधान के अनुच्छेद 191 में विधानसभा की सदस्यता लिये निरर्हतायों (Disqualifications) का उल्लेख है, उसके उप प्रावधान (1)(ई) में उल्लेख है कि यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा निरर्हित कर दिया गया हो। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान है कि मतदाता सूचियों के मामलों में जो व्यक्ति अपराध करता है और उसे 2 साल या अधिक की सजा होती है तो वह अयोग्य घोषित होगा, तथा यदि वह अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो स्वतः विधानसभा की सीट संविधान के अनुच्छेद 190 के अनुसार रिक्त घोषित मान ली जावेगी।

वस्तुतः विपक्ष नेता राहुल गांधी का केस है कि केन्द्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों में गडबडी की है, सही मतदाताओं के नाम काटे हैं जीवित व्यक्तियों को मृतक बना दिया है। दो–दो स्थानों पर नाम दर्ज किये हैं आदि। इस कार्यवाही को वे वोटों की चोरी की संज्ञा दे रहे हैं, जबकि यह केस चोरी का नहीं है। उन्होंने इस हेराफेरी का न तो कोई सबूत दिया और न कोई शहादत दी जिससे वे आरोपों को साबित कर सकें। इस कारण से राहुल जी से चुनाव आयोग ने रूल 20(3)(बी) के अनुसार शपथ–पत्र देने को कहा था और उन्होंने न तो शपथ–पत्र दिया और न सबूत और मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। अतः चुनाव आयोग ने कहा कि उनके आरोप आधार रहित हैं। प्रश्न है चुनाव आयोग अब क्या कदम उठाता है, यह हमें देखना है। हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

लेखक का अपना विचार है कि संसद को एक कानून बनाना चाहिए, जिसमें प्रावधान हो कि यदि कोई देश का नागरिक संवैधानिक कर्तव्यों की पालना नहीं कर रहा है तो उसे चुनाव में खडे होने के हेतु क्पेन्सपलिट (अयोग्य) करार दिया जावे। अनुच्छेद 51क स्पष्ट करता है भारत के नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान की पालना करे उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। प्राणी मात्र के प्रति दया (करुणा भाव) रखे और सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करे। हिंसा से दूर रहे। क्या चुनू हुये सांसदों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे संसद को अपना कर्तव्य निभाने दें। गत दिनों संसद में जो हुआ है, क्या ऐसा करने के हेतु हमने अपने सांसद चुनकर भेजे हैं। देश हम सबका है, केवल विपक्ष का नहीं है। देश कभी भी बांग्लादेश व म्यांमार के नागरिक को जो देश में चुस आये हैं, अवैध प्रवासी हैं, उन्हें एक व्यक्ति एक चुनाव के नारे से मतदान में भाग नहीं लेने दे सकता है। मतदाता तो वही होगा जो अनुच्छेद 326 के अनुसार देश का नागरिक है। उसे ही वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव में मतदान करने का अधिकार है।

सबको सम्मति दे भगवान्‌!

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

“एक पेड़ माँ के नाम-2.0 अभियान” शिक्षा विभाग ने 4.1 5 करोड़ पौधे लगाये विद्यार्थियों में पर्यावरणीय जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना का हो रहा विकास



डॉ. अमृता कटारा

जयपुर, 27 अगस्त। राजस्थान की रेतिली धरती को हरी चादर ओढ़ाने का संकल्प लिए हरियालो राजस्थान अभियान अब एक जनआंदोलन का रूप लेता जा रहा है। यह सिर्फ पौधारोपण तक सीमित नहीं, बल्कि हरियाली के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी निरंतर प्रयास है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाने के ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल करने के बाद अब अब लक्ष्य रखा है कि आने वाले वर्षों में पौधारोपण को और अधिक संगठित और वैज्ञानिक ढंग से किया जाए। इसके तहत पौधों की जियो-टैगिंग, नमी संरक्षण के लिए गड्डों में जल संचरना और ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक अपनाई जा रही है । स्कूल, कॉलेज और पंचायत स्तर तक

राज्य सरकार के प्रयासों के साथ-साथ आमजन की भागीदारी को अभियान का सबसे बड़ा आधार बनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने अब अगले पांच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इसके लिए पौधारोपण को संगठित, तकनीकी और दीर्घकालिक स्वरूप देने पर जोर है। विद्यालयों के साथ

पौधारोपण को उत्सव की तरह मनाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हरियालो राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य में शिक्षा विभाग द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत शिक्षा विभाग द्वारा पौधारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति में 4.15 करोड़ पौधों का पौधारोपण कर प्रथम स्थान हासिल किया गया है। राज्य में शिक्षा विभाग विद्यार्थियों को केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें सामाजिक एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्वों से जोड़ने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान शिक्षा विभाग के मंत्री मदन दिलावर के नेतृत्व में पूरे राज्य में सफलतापूर्वक संचालित किया गया। यह पहल शिक्षा और पर्यावरण को साथ लाकर भविष्य की पीढ़ी को संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में मील का पथर साबित हुई।

राज्य सरकार के प्रयासों के साथ-साथ आमजन की भागीदारी को अभियान का सबसे बड़ा आधार बनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने अब अगले पांच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इसके लिए पौधारोपण को संगठित, तकनीकी और दीर्घकालिक स्वरूप देने पर जोर है। विद्यालयों के साथ

महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, युवा संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएँ और उद्योग जगत भी इस पहल से जुड़ रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में वृक्ष ही जीवनेरेखा हैं। इनसे न सिर्फ मिट्टी का कटाव रुकेगा बल्कि भूमिगत जलस्तर भी सुधरेगा। साथ ही यह जैव-विविधता और वन्यजीव संरक्षण में भी अहम योगदान देंगे। हरियालो राजस्थान अभियान से प्रदेश को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। पौधों से होने वाले औषधीय, औद्योगिक और फल-फूल उत्पादन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी होगा और ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेंगे।

हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हुआ पार- मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कि इस साल हमारा 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था और सभी के सामूहिक प्रयासों से हमने इस लक्ष्य को पार कर लिया है और अब तक 10 करोड़ 21 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्षा काल अभी चल रहा है, ऐसे में विभाग इस अभियान के तहत लोगों को अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें। श्री शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेशवासियों की पर्यावरण

के प्रति जागरूकता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत आमजन से ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण की अणील की।

विद्यार्थियों में पर्यावरणीय जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना का हो रहा विकास-स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने इस अवसर पर सभी अध्यापक एवं विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि “हरियालो राजस्थान” केवल एक अभियान नहीं, बल्कि प्रकृति और भविष्य से किया गया वादा है। जिस प्रकार 4.15 करोड़ पौधारोपण का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल हुआ है, उसी तरह यदि हर नागरिक एक पौधे को जीवनभर संजोने का संकल्प ले, तो राजस्थान निश्चित ही हरियाली की नई मिसाल बनेगा। उन्होंने अपील कर कहा कि हम सब मिलकर यह प्रण लें – एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ आने वाली पीढ़ी के नाम लगाएँ। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत न केवल विद्यार्थियों में पर्यावरणीय जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना का विकास होगा बल्कि शिक्षा विभाग और वन विभाग के संयुक्त प्रयासों से राजस्थान में हरित आवरण में भी वृद्धि होगी, वहीं

तकनीक आधारित पारदर्शी रिपोर्टिंग और सामुदायिक भागीदारी भी सुनिश्चित होगी।

गौरतलब है कि इस अभियान के तहत सभी पौधों को जियो टैगिंग के माध्यम से हरियालो राजस्थान ऐप पर दर्ज किया जा रहा है ताकि पौधारोपण के साथ पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में भी सतत प्रयास किये जा सकें, साथ ही ब्लॉक एवं जिला स्तर पर आंकड़ों की पारदर्शिता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। प्रत्येक स्कूल की अभियान से जुड़ी गतिविधियों की रिपोर्टिंग शाला दर्पण एप के माध्यम से की जा रही है। वहीं विद्यार्थियों, शिक्षकों और विद्यालय स्तर की भागीदारी को सुनिश्चित कर विद्यालय-वार पौधारोपण प्रगति की डिजिटल ट्रैकिंग भी निरंतर की जा रही है। “एक पेड़ माँ के नाम 2.0” के तहत शिक्षा विभाग द्वारा पौधारोपण ऐसी पहल है, जो शिक्षा को केवल कक्षा तक सीमित नहीं रखती बल्कि प्रकृति और समाज से भी जोड़ती है। अभियान के तहत विद्यालयों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से आग्रह किया गया है कि इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और राजस्थान को हरित राजस्थान बनाने में योगदान दें।

—**डॉ. अमृता कटारा, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, डीआईपीआर, जयपुर**

आत्मा के स्वाभाविक धर्म : दशलक्षण धर्म विश्वशांति का उद्घोषक



भागचंद जैन मिश्रपुरा

जैन धर्म अनादि, अनंत, शाश्वत, सनातन धर्म है। इस युग के जैन धर्म प्रवर्तक वर्तमान अवसरपिणी काल के प्रथम अर्थकार आदिनाथ भगवान्‌ है। जैन धर्म के तीन प्रमुख पर्व वर्ष में तीन बार मनाए जाते हैं। 1) षोडश कारण भावना पर्व का पालन करने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव (बंधन) होता है। 2) अष्टान्हिका पर्व सिद्धों की भक्ति का पर्व मनाने से आत्म शुद्धि होती है एवं 3) – दशलक्षण पर्व- इस पर्व को बड़े ही भक्तिभाव के साथ मनाया जाता है। भाद्रपद में आने वाले इस पर्व के दौरान आत्मा के दस धर्मों की विशेष आराधना करते हैं। दस धर्मों का पालन करना साधकों, तपस्वियों के मूल गुण है। श्रावकगण भी आत्म कल्याण के दस धर्मों का पालन करने की चेष्टा करते हैं। दशलक्षण पर्व आत्मानुभूति का मार्ग प्रशस्त करता है, इसको पर्वराज भी कहा जाता है। जैन धर्म में इस पर्व का महत्वपूर्ण स्थान है।

दशलक्षण धर्म पर्व, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, में दस धर्मों की पूजा, आराधना एवं पालना की जाती है, वे दस धर्म इस प्रकार हैं:

1) उत्तम क्षमा: दूसरों को क्षमा करना और स्वयं की गलती के लिए दूसरों से क्षमा मांगना।

2) उत्तम मार्दव : विनयशील, विनम्र, कोमल भाव रखना।

3) उत्तम अर्जुनः मन की शुद्धता, सरलता बनाए रखना एवं छल-कपट से दूर रहना।

4) उत्तम शौच : पवित्र भावना एवं मन, वचन और शरीर की शुद्धि रखना।

5) उत्तम सत्य : सच बोलना और सच का पालन करना ही सत्य धर्म नहीं है। आत्मा से जो शांति स्वरूप वीतरागता उत्पन्न होती है, वहीं सत्य धर्म है।

6) उत्तम सम्मति : अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण अर्थात आत्म नियंत्रण प्राप्त करना।

7) उत्तम तपः आंतरिक एवं बाह्य 12 प्रकार के तप धारण कर कर्मों का नाश करना।

8) उत्तम त्याग : वास्तविकता में त्याग से प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, देने के सुख का अनुभव होता है।

9) उत्तम अकिंचनः वस्तुओं और व्यक्तियों से आसक्ति न रखना।

10) उत्तम ब्रह्मचर्यः अपने आत्म स्वरूप में रमण करना।

इन दस धर्म में से प्रथम तीन लक्षण भाव धर्म, आगे के पांच लक्षण मोक्ष मार्ग प्राप्ति के उपाय एवं अंतिम दो लक्षण धर्म का सार है।

इनकी पालना कर आत्म शुद्धि की जाती है एवं आत्मानुशासन की ओर अटसरत होते हैं।इन सभी धर्मों के अंगरुणि नाम से ही स्वतः स्पष्ट है। ये सभी धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी एक धर्म की पालना, साधना करने से शेष सभी धर्म आत्मसात हो जाते हैं एवं साधक के जीवन का अंग बन जाते हैं। उत्तम शब्द सत्यच दर्शन के साथ इन गुणों को प्राप्त करने के अर्थ में लिया गया है। आत्मा के सत्य स्वरूप को प्रकट करने के कारण उत्तम धर्म कहा जाता है एवं उत्तम धर्म ही मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। यह पर्व जिन मंदिरों में विशेष पूजा के साथ बड़े ही भक्तिभाव से मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान जैन धर्मावलंबी सामान्यतः व्यापार एवं नौकरी से अवकाश पर रहते हैं। इन दस धर्मों में जिन अभिरुचि, शांतिधार, पूजा, पाठ, स्वाध्याय यथावत करते हैं। प्रतिदिन नित्य नियम पूजा के साथ सभी दस धर्मों की पूजा विधान है, किंतु महत्ता की दृष्टि से प्रत्येक दिन क्रमशः अलग अलग धर्म के गुणों का विशेष वर्णन सूक्ष्मतम रूप में पूजा करने के अंग आत्मसात् किया जाता है।

इस पर्व में जैन धर्मावलंबी साधना के मार्ग को अपनाते हुए व्रत, उपवास

रखते हैं एवं कई भक्त दस दिनों तक अन्न जल ग्रहण ही नहीं करते हैं एवं इस पर्व में भोजन करने वाले सात्विक भोजन ही सीमित मात्रा एवं आवृति में ग्रहण करते हैं।

श्रावकगण इस समय का सदुपयोग त्याग, तपस्या, आराधना, साधना का मार्ग अपना कर करते हैं। यह पर्व अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, आत्मशुद्धि एवं कर्मों का क्षय कर मोक्षमार्ग प्रशस्त करने के लिए मनाया जाता है। यह पर्व यथाशक्ति दान देने की प्रेरणा भी देता है। इस पर्व के अंत में जाने अनजाने में की गई गतियों के लिए क्षमावानी पर्व मनाया जाता है।

जीवन को सर्वोत्तम तरीके से जीने की कला सिखाने वाले दस धर्मों को व्यवहार में उतारने का पर्व दशलक्षण महा पर्व है। उल्लेखनीय है कि इन दस धर्मों पर जैन धर्मावलंबियों का एकाधिकार नहीं है, कोई भी इन्हें अपनाकर मोक्षमार्ग प्रशस्त कर सकता है। दस धर्मों में आत्मिक शांति के साथ वैश्विक शांति निहित है। अपनाकर तो देखिए। श्वेतांबर संप्रदाय में यह पुरुषेण पर्व के नाम से आद दिन के लिए मनाया जाता है, जो इस वर्ष 20/08/25 से 27/08/25 तक मनाया गया है।

दस धर्म की पालना क्यों ?
भारतीय संस्कृति विभव में निराली है। यहां हर धर्म समाज में सद्भावना बनी रहती है। यहां के त्यौहार तारकिक आधार पर मनाए जाते हैं। उनको अपनाने में प्राणी मात्र के साथ समाज एवं राष्ट्र कल्याण निहित होता है। जीवन किसी भी प्रकार से जिया जा सकता है, लड़ाई झगड़ा करके, सामंजस्य के साथ या सद्भावना यानी एक दूसरे का मंतव्य समझते हुए। भाद्रपद मास में आने वाला दस धर्मों का पर्व भी बहुत सारे संदेश छिपे हुए है। दस दिन तक लगातार जब व्यक्ति भक्ति, पूजा पाठ, स्वाध्याय एवं नियमित रूप से आत्म चिंतन, ध्यान करता है, शुद्ध एवं सात्विक भोजन वह भी सीमित मात्रा में ग्रहण करता है तो इसका दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिकता जीने की एक कला है। इस दौरान मुनिसंघों के सानिध्य में विभिन्न स्थानों पर आध्यात्मिक, ध्यान

	मेघ
	परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

	वृष
	विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। किसी भी कारण से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

	मिथुन
	कार्य में शुभ-सांगतिक कार्यों का सम्पन्न हो सकते हैं। समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

	कर्क
	घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

	सिंह
	परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

	कन्या
	आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन संदेश रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक प्रगति होगी।

	तुला
	व्यावसायिक व्यस्तता अभी उत्पन्न बनी रहेगी। नौकरोंपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

	वृश्चिक
	घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अनर्गल कार्यों में समय ख़राब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रहे।

	धनु
	आर्थिक/वित्तीय मामलों में सतुलन बना रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

	मकर
	व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बरने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

	कुंभ
	व्यावसायिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। नौकरोंपेशा व्यक्तियों को भावदौड़ रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होगा।

	मीन
	चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नवीन कार्यों के लिए दिन ठीक नहीं है।

राजस्थान अपार संभावनाओं का प्रदेश, निवेशक राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बनें : मुख्यमंत्री

बिजली-पानी-रोजगार क्षेत्र में हमने लिए हैं अभूतपूर्व निर्णय : भजनलाल शर्मा

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि समृद्ध, सशक्त और सर्वापरि राज्य बनाने की प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। उन्होंने उधिमयों से आल्हान किया कि उद्यमी अधिक से अधिक निवेश कर राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बनें। शर्मा गुरूवार को जयपुर में इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा तथा व्यापारिक दृष्टि से अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन से राज्य सरकार को 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, इनमें से 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर धरातल पर काम शुरू हो गया है।

उन्होंने कहा कि उद्योगों को अधिक सुगम बनाने के लिए राज्य में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान मिनरल पॉलिसी, रीको प्रत्यक्ष आवंटन नीति, डेटा सेंटर नीति, वस्त्र एवं परिधान नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति जैसी नीतियां जारी की गई। शर्मा ने कहा कि राजस्थान ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी में देशभर में नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

देश के कुल खनिज ब्लॉक आवंटन का 20 प्रतिशत अकेले राजस्थान से हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने विजन डॉक्यूमेंट-2047 को मंजूरी दी है। यह केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि राजस्थान के सुनहरे



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को जयपुर में इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 को संबोधित किया।

भविष्य का खाका है। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक राजस्थान 350 बिलियन डॉलर और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 सौर परियोजनाओं को मंजूरी, नई भूमि आवंटन नीति, पंच गौरव जैसे नवाचारों एवं निर्णयों से ऊर्जा एवं उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिए निरंतर निर्णय ले रही है। जोधपुर-पाली औद्योगिक गलियारा, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो 19 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में

50,000 प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा वस्त्र, कृषि, इंजीनियरिंग और ऑटो क्लस्टर उद्योगों पर केंद्रित यह परियोजना राजस्थान को औद्योगिक मानचित्र पर नया स्थान दिलाएगी। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 जारी की गई है, जो 2030 तक प्रदेश के अक्षय ऊर्जा उत्पादन को 125 गीगावाट के स्तर तक ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है तथा 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने

■ “राइजिंग राजस्थान समिट में राज्य सरकार को 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, इनमें से 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर धरातल पर काम शुरू हो गया है।”

कहा कि हमने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए ‘एक पेड़ मां के नाम अभियान’ से प्रेरणा लेते हुए ‘हरियालो राजस्थान’ की शुरुआत की है। अभियान के तहत 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है तथा अब तक हम 17 करोड़ से अधिक पौधे लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में असीमित अवसरों के साथ प्राकृतिक संसाधन एवं कुशल मानव संसाधन मौजूद हैं।

राज्य सरकार ने पिछले डेढ़ साल में पानी, बिजली, बुनियादी ढांचे और प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। पेयजल और सिंचाई की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, माही बांध योजना सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं। साथ ही, हमने 5 साल के कार्यकाल में युवाओं को 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण, 1 हजार 300 गांवों को डामर

सड़कों से जोड़ना, मिसिंग लिंक रोड का निर्माण, जयपुर एयरपोर्ट का विस्तार सहित विभिन्न कार्यों से राज्य में विकास के नए मानदंड स्थापित किए जा रहे हैं।

ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऊर्जा के क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा तथा ट्रांसमिशन तंत्र को विकसित करने से इस क्षेत्र में बहुत तेजी से कार्य हो रहा है। हमारा संकल्प है कि हम किसान को 2027 तक दिन में बिजली देंगे।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के सदस्य प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि राजस्थान सरकार सुशासन का पर्याय बन चुकी है। वर्तमान सरकार जिम्मेदारी, जवाबदेही और उत्तरदायित्व के साथ कार्य कर रही है। यह पहला ऐसा राज्य है, जिसने अपने कार्यकाल के शुरुआत में ही निवेश समिट का आयोजन किया, साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा सतत विकास को बढ़ावा देते हुए हरियालो राजस्थान, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जैसे नवाचार भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार चार गुना शक्ति के साथ राजस्थान को आगे ले जा रही है। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहानी गैस सुरेश पी. मंगलानी, निदेशक एवं सहसंस्थापक एस.ए.ई.एल. इंडस्ट्रीज लि. सुखबीर आवला सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने समिट में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग अजिताभ शर्मा सहित बड़ी संख्या में उद्यमी और गणमान्य मौजूद रहे।

जेल में फिर मिला मोबाइल और सिम

जयपुर। राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल में मोबाइल और सिम मिलने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। अब एक बार फिर जेल में मोबाइल और सिम मिलने से हड़कंप मच गया। जेल में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान मोबाइल और सिम लावारिस हालत में मिले हैं। इस संबंध में जेल प्रशासन की ओर से लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। थानाधिकारी बन्नालाल ने जेल अधीक्षक की ओर से मामला दर्ज करवाया है कि 27 अगस्त को जेल प्रशासन की ओर से सघन तलाशी अभियान चलाया गया था। इस दौरान दो नंबर वार्ड के बैरक नंबर 2 में टॉयलेट के पास एक सिल्वर कलर का छोटा कीपैड मोबाइल और सिम मिली है। इस पर जेल कर्मचारियों ने उच्चाधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी।

करीब 38 हजार रोगियों ने आरजीएचएस योजना के तहत उपचार प्राप्त किया है। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने बताया कि जिन अस्पतालों ने उपचार बंद कर रखा है, उनके प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद जारी है।

हमारा प्रयास है कि सभी अस्पताल योजना के तहत सेवाएं उपलब्ध कराएं। निजी अस्पतालों व सभी हितधारकों से चर्चा कर योजना में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। गड़बड़ी पर अंकुश लगाकर योजना का निबांध संचालन विभाग की प्राथमिकता है।

‘आर.जी.एच.एस. में 3 5 0 अस्पतालों ने जारी रखीं सेवाएं, 3 8 हजार रोगियों को मिला उपचार’

जयपुर (कासं)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खीवसर ने कहा है कि राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के सुचारु संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। रोगियों को योजना का लाभ लेने में किसी तरह की बाधा नहीं आए, इस दिशा में हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजना में जरूरी बदलाव कर इसे बेहतर बनाया जाए, ताकि लाभार्थियों को सुगमता से उपचार मिले। इसके लिए प्रुफ फुल सिस्टम विकसित किया जा रहा है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि गुरूवार को भी प्रदेश के

■ राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल का कहना है कि, “जिन अस्पतालों ने आर.जी.एच.एस. में उपचार बंद कर रखा है, उनके प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद जारी है। हमारा प्रयास है कि सभी अस्पताल योजना के तहत सेवाएं उपलब्ध करवाएं।”

ज्यादातर निजी अस्पतालों में आरजीएचएस योजना के तहत सुचारु रूप से उपचार मिला। उन्होंने बताया कि करीब 350 अस्पतालों में ओपीडी, डे केयर एवं आईपीडी में रोगियों ने उपचार प्राप्त किया। प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध सभी अस्पतालों में आरजीएचएस योजना के तहत उपचार मिल रहा है।

राठौड़ ने कहा कि निजी अस्पतालों के साथ-साथ राजकीय चिकित्सा संस्थानों में भी योजना के तहत उपचार के लिए सभी माकूल इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं, ताकि जहां भी निजी अस्पतालों में उपचार बंद हों, वहां राजकीय चिकित्सा संस्थानों में रोगी सुगमता से उपचार प्राप्त कर सकें। विगत 4 दिवस में

शाही ठाठ-बाट के साथ जयपुर भ्रमण पर निकले गणेशजी महाराज

मोतीढूंगरी मंदिर से शुरू हुई शोभायात्रा में 50 से अधिक झांकियां शामिल हुईं

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। मोती ढूंगरी गणेश जी मंदिर से श्री गणेश जन्मोत्सव के अंतर्गत गज पूजन के साथ 38वीं शोभायात्रा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आरती कर शोभायात्रा को रवाना किया। यह पारंपरिक शोभायात्रा गढ़ गणेशजी मंदिर तक निकाली जाती है।

■ ऑपरेशन सिंदूर एस 400 मिसाइल की तर्ज पर निकाली गई शोभायात्रा रही आकर्षण का केन्द्र

शोभायात्रा में चित्रस्वरूप भगवान श्री गणेश की विधिवत रूप से पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मोती ढूंगरी श्री गणेश मंदिर में दर्शन भी किए। जहां महंत कैलाश शर्मा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं से आत्मीयता के साथ मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस अवसर पर सांसद मंजू शर्मा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण और गणमान्यजन उपस्थित रहे।

शोभायात्रा में आगे ध्वज लिए हाथी को रवाना किया गया। इसके साथ ही शोभायात्रा में 4 हाथी, 11 ऊंट और 21 घोड़े लगाजमे में शामिल हुए । शोभायात्रा की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित थी। इसी के साथ शोभायात्रा में 50 से अधिक झांकियों का संचालन



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मोती ढूंगरी गणेश मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना के बाद शोभायात्रा को रवाना किया। इस दौरान “ऑपरेशन सिंदूर” थीम पर सजाई गई झांकी आकर्षण का विशेष केन्द्र रही।

किया गया। भव्य शोभायात्रा में राम मंदिर में दर्शन का तांडव नृत्य, रामलला के गणेश, राम-रावण युद्ध, महाभारत का लेखन, शिव-पार्वती के प्रसंग, माता वैष्णो देवी दरबार, महाकाल, छत्रपति शंभाजी महाराज, केदारनाथ धाम, शेखावाटी की सांस्कृतिक झलक और संत परंपराओं को भी प्रदर्शित किया गया। मंदिर समिति के अनुसार, भगवान गणेश की झांकियां स्वचालित तकनीक से भी सजाई गईं। इनमें गणेशजी का तांडव नृत्य, रिद्धि-सिद्धि संग नृत्य, मृषक पर सवारी, महाकाल रूप, और मोबाइल की लत से दूर रहने का संदेश जैसी झलकियां प्रमुख रही। एक झांकी में भगवान शंकर की पीठ पर गणेश जी सवारी करते हुए दिखाए गए।

स्वरूपों के साथ-साथ अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन, राम-रावण युद्ध, महाभारत का लेखन, शिव-पार्वती के प्रसंग, माता वैष्णो देवी दरबार, महाकाल, छत्रपति शंभाजी महाराज, केदारनाथ धाम, शेखावाटी की सांस्कृतिक झलक और संत परंपराओं को भी प्रदर्शित किया गया। मंदिर समिति के अनुसार, भगवान गणेश की झांकियां स्वचालित तकनीक से भी सजाई गईं।

इनमें गणेशजी का तांडव नृत्य, रिद्धि-सिद्धि संग नृत्य, मृषक पर सवारी, महाकाल रूप, और मोबाइल की लत से दूर रहने का संदेश जैसी झलकियां प्रमुख रही। एक झांकी में भगवान शंकर की पीठ पर गणेश जी सवारी करते हुए दिखाए गए।

काशी की प्रसिद्ध मसाने की होली की झांकी भी सजाई गई। गणेश जी के महाभारत लिखने की झांकी सजाई गई। इस झांकी में आदि शिव को भी दिखाया गया है। शोभायात्रा समिति के संयोजक भानु प्रताप ने बताया- इस बार बहुत विशेष झांकियों का आयोजन किया गया है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर की झांकी और मिसाइल एस 400 भी शामिल है। यह वही मिसाइल है, जिसने पाकिस्तान में जाकर तबाही मचाई। इसके अलावा राजस्थान की संस्कृति को दिखाती हुई झांकी भी शामिल की गई है। इसमें त्रिपालिया गेट से निकलने वाली तीज माता की सवारी की झांकी भी शामिल है।

‘नेता प्रतिपक्ष जूली की सहमति से 2 9 के बजाय 2 8 को रखी सर्वदलीय बैठक, फिर भी कांग्रेस ने किया बहिष्कार’

विधानसभा के मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर वासुदेव देवनानी ने गुरूवार को बुलाई थी यह सर्वदलीय बैठक

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। विधानसभा का मानसून सत्र सुचारू रूप से चलने के लिए गुरूवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। कांग्रेस ने यह कहते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया कि यहां एक तरफा फैसला लिए जाते हैं।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक 2 सितंबर को होगी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे।

वहीं दूसरी ओर बैठक के बहिष्कार पर सत्ता पक्ष ने कहा कि, विपक्षी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। बहिष्कार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि सर्वदलीय बैठक से पहले सभी पक्षों से सहमती ली जाती है। आज की डेट टीकाराम जूली से पूछकर ही तय की गई थी। वे 29 अगस्त को आने में असमर्थ थे, इसलिए जूली के कहने पर 28 अगस्त डेट तय की गई। अचानक उन्होंने सूचना दी कि वे और उनके सचेतक भी नहीं आएंगे। ऐसा करना मैदान छोड़ने वाली बात हुई। गर्ग ने कहा कि जानबूझकर बहिष्कार किया है। इसके कारण अभी तक हमको समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की आपस की लड़ाई, डोटसरा वर्सेस जूली की वजह से ये सब कुछ हो रहा है।

गर्ग ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है,

■ सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि, “नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अचानक सूचना दी कि वे और उनके सचेतक बैठक में नहीं आएंगे। ऐसा करना मैदान छोड़ने वाली बात हुई। मुझे लगता है कि कांग्रेस की आपस की लड़ाई, “डोटसरा वर्सेस जूली” की वजह से ये सब कुछ हो रहा है।”

इसकी निंदा करते है। जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विधानसभा को लेकर शुरुआत से ही भाजपा सरकार की मंशा अच्छी नहीं रही है। विधानसभा अध्यक्ष चाह रहे हैं कि सत्र लम्बा चले, लेकिन सरकार चाह रही है कि कुछ दिन में ही विधानसभा सत्र खत्म हो जाए, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित न हो सके। विधानसभा में भी कई वाक्ये ऐसे हुए हैं जो एक पक्षीय रहे। हमारे विधायक नरेन्द्र बुढ़ानिया को विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया, लेकिन अचानक से उन्हें कुछ दिन में ही हटा दिया गया। इतने वरिष्ठ सदस्य के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। जूली ने कहा कि

विधानसभा में सवालों के जवाब पहले जनता के लिए पोर्टल पर अपलोड होते थे, जो इस बार अपलोड नहीं किए गए। क्या सरकार को कोई डर है? जूली ने कहा कि इसी प्रकार जिलों में हमारे प्रधानों, प्रमुखों, चेयरमैनो को चुन-चुनकर हटाया जा रहा है। सरकार के एक विधायक ने जनता के बीच कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में सभी

उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया

जयपुर। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एसआई भर्ती परीक्षा - 2021 को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। क्योंकि करीब 500 लोग नकल माफिया के साथ सौदा कर परीक्षा में पास हुए। ये लोग पुलिस जैसे सेवेदनशील विभाग में एसआई बनकर जनता के साथ क्या न्याय करते एवं कैसे कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग देते। मैंने पहले दिन से ही एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की थी, क्योंकि मेरे पास एसआई पेपर लीक होने के पक्के सबूत थे। मैंने पूर्ववर्ती सरकार के समय एसओजी को ये सभी सबूत दिए। मैंने जैसे ही सबूत दिए वे सही निकलते गये, जिसके लिए आभारन किए, लेकिन पूर्व सरकार की नकल माफिया से सांठगांठ थी।

जवाहर कला केन्द्र में “चित्रायण: जर्नी थ्रू आर्ट” का शुभारंभ

जयपुर। जयपुर के जवाहर कला केन्द्र स्थित अलंकार आर्ट गैलरी में संयुक्त कला प्रदर्शनी “चित्रायण: जर्नी थ्रू आर्ट” का भव्य शुभारंभ हुआ। यह प्रदर्शनी चार प्रतिभाशाली महिला कलाकारों - निधि चौधरी, निकिता

■ चार प्रतिभाशाली महिला कलाकारों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन

टाटेर, पारिधि जैन और शगुन अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। प्रदर्शनी का उद्घाटन वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा किया गया।

इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों और कला प्रेमियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी राजस्थान की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी हुई है, साथ ही विश्वभर की यात्राओं से मिली प्रेरणाओं को भी दर्शाती है। शगुन अग्रवाल, जो मनोविज्ञान में प्रशिक्षित हैं और बचपन से कला से जुड़ी रही हैं, अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से बदलते मानसिक परिदृश्यों



चार प्रतिभाशाली महिला कलाकारों निधि चौधरी, निकिता टाटेर, पारिधि जैन और शगुन अग्रवाल की ओर से जवाहर कला केन्द्र में संयुक्त कला प्रदर्शनी ‘‘चित्रायण: जर्नी थ्रू आर्ट’’ प्रदर्शित की गई है।

को अभिव्यक्त करती हैं। उनकी कला श्रृंखला ए जर्नी इन्वॉड आत्मा-वेषण और आत्मसंवाद की गहरी झलक देती है। शगुन अपने पॉइंटकार्ट ‘शेरदिल्ली’ के जरिये भी व्यक्तिगत और

मांग पत्र जारी किए जा सकेंगे। मांग पत्र जमा होने के बाद आवेदकों को तुरंत प्राथमिकता से कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। मौजूदा समय में कृषि कनेक्शन नीति-2017 के अन्तर्गत सामान्य रूप के कृषि कनेक्शन के आवेदकों की क्षमता के अनुसार 33/11 केबी से निकलने वाले फीडरों पर कृषि कनेक्शन के लिए हिमांशु नोट जारी किए जाते हैं। मांग पत्र

वर्तमान में 22 फरवरी 2022 तक की कट ऑफ डेट के अनुसार सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कनेक्शन देय हैं। राज्य में फिलहाल 78 हजार 498 कृषि कनेक्शन लंबित हैं, जिनमें डिमाण्ड नोट जमा किए जा चुके हैं।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग की, वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को राजस्व में बढ़ोतरी के लिए प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के लिए निर्देश दिए।

‘सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित होगी’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने यह भी कहा कि अनियमितता पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी

जयपुर, 28 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क, बायपास, आरओबी और आरयूबी जैसी जनउपयोगी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में घंटिया सामग्री का उपयोग पाए जाने और अकारण देरी पर कॉन्ट्रक्टर के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए उससे वसूली की जाएगी। साथ ही, अनियमितता पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त

- मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में मानचून में क्षतिग्रस्त सड़कों का ड्रोन सर्वे करारकर 20 अक्टूबर से पहले मरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश दिये।**

कार्यवाही होगी।

मुख्यमंत्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2025–26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानचून

के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का ड्रोन सर्वे करवाकर 20 अक्टूबर से पहले मरम्मत कार्य पूरा करवाया जाए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग को बेहतर सड़क निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री की सूची संधारित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व में बढ़ोतरी के

लिए प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सड़क, बायपास आदि के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण पर उन नीतियों पर विचार करें जिसमें विभाग को भविष्य में राजस्व की बढ़ोतरी हो। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभागीय प्रोजेक्ट्स एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।

बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे का फार्मूला तय

चर्चा है कि जेडीयू 102, भाजपा 101, चिराग पासवान 20, मांझी व उपेन्द्र कुशवाह 10-10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे

- कहा जा रहा है कि सीटों का बंटवारा तो लाभभग तय हो गया है, पर कौन सी पार्टी किस सीट से लड़ेगी, इस पर चिंतन जारी है।**

गठबंधन की सीट शेर्यरिंग की तस्वीर अब काफी साफ हो गई है। लेकिन कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर लड़ेगी इसका मंथन आगे होगा। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली गए थे। इस बंटवारे अब सीटों का ये आंखड़ा आया है। जेडीयू को अधिक सीटें देकर यह बतावे की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है।

छत्तीसगढ़ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
2000 से अधिक लोगों का अस्थायी रूप से पुनर्वासित किया गया है। शिविरों में रहने, खाने और सोने की संपूर्ण व्यवस्था की गई है।

अमेरिकी वीजा की अवधि घटाई जाएगी?

वाशिंगटन, 28 अगस्त। अमेरिकी प्रशासन अपने वीजा नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रहा है और अगर ये नियम स्वीकृत हो जाते हैं तो इससे अमेरिका में रह रहे वीजा धारकों की समयावधि घट जाएगी। इससे वहां रह रहे लोगों खासकर छात्रों को अपने देश जल्द वापस लौटना पड़ सकता है।

अमेरिकी गृह विभाग ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि ये प्रस्तावित नियम अगर स्वीकार हो जाते हैं तो इससे वीजा के दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा और शासन की इन व्यक्तियों की जांच और निगरानी करने को क्षमता बढ़ेगी। यह नियम कुछ ही तरह की वीजा श्रेणी पर लागू होगा और इस श्रेणी में विदेशी छात्रों

- अगर ऐसा हुआ तो वहां काम या पढ़ाई के लिए गए लोगों को जल्दी ही लौटना पड़ सकता है।**

को मिलने वाला वीजा भी शामिल है। अमेरिका के गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, “बहुत लंबे समय से, पिछले प्रशासनों ने विदेशी छात्रों और अन्य वीजा धारकों को लगभग अनिश्चित काल तक अमेरिका में रहने की अनुमति दी है, जिससे सुरक्षा जोखिम पैदा होता है।” विदित हो कि सन 1978 से, यहां आने वाले विदेशी छात्रों को एच श्रेणी का वीजा एक खास अवधि के लिए दिया जाता रहा है। अन्य वीजा श्रेणी से भिन्न यह वीजा धारकों को बिना किसी अतिरिक्त जांच-पड़ताल के अनिश्चित काल तक अमेरिका में रहने की अनुमति देता है। अब अमेरिकी प्रशासन को लगता है कि विदेशी छात्रों ने अमेरिकी उदारता का लाभ उठाया है और वे ऐसे “स्थायी” छात्र बन गए हैं, जो अमेरिका में रहने के लिए उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में स्थायी रूप से खुद का नामांकन किए रहते हैं।

बिहार में घुसे तीन संदिग्धों पर 5 0 हजार का इनाम घोषित

तीनों पाकिस्तानी संदिग्ध नेपाल की सीमा से बिहार में घुसे हैं राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है

- इस घटनाक्रम के बाद राहुल की वोट अधिकार यात्रा में भी बदलाव किया गया है अब वे खुली जीप की बजाय बंदगाड़ी से यात्रा कर रहें हैं।**

शामिल हैं। पुलिस की ओर से इन तीनों संदिग्धों के नाम, तस्वीर सार्वजनिक कर दिये गये हैं।

पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों को खुफिया तंत्र को एक्टिव रखने, इनपुट जुटाने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है।

वहीं मोतिहारी पुलिस ने तीनों आतंकियों पर 50 हजार रुपए इनाम की घोषणा की है। बिहार में घुसे तीनों आतंकियों का पासपोर्ट भी सामने आया

मोदी जापान और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
देशों के प्रमुख से होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के निमंत्रण पर मैं 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान की दो दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूँ। हम इस यात्रा के दौरान अपनी वैश्विक रणनीतिक और वैश्विक सझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर ध्यान देंगे। यह यात्रा हमारे सभ्यतागत बंधनों और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने का भी अवसर

होगी जो हमारे लोगों को परस्पर जोड़ते हैं।(पीएम ने कहा कि जापान से मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाऊंगा। भारत एससीओ का सक्रिय और रचनात्मक सदस्य है। सात साल में चीन की अपनी पहली यात्रा के दौरान पीएम दुनिया की कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ नजदीकी बंध।कर मैक मैक इन ईशिया पहल के लिए समर्थन जुटाएंगे।

‘वैश्विक नेताओं से निजी ...

- इसके लिए भारत पर हर तरफ से दबाव डाला जा रहा है। कभी टैरिफ बढ़ाकर कभी एच वन-बी वीजा के नाम पर तो कभी ऑपरेशन सिंदूर व सीज़फायर पर दावे करके तो कभी रुस -यूक्रेन जंग को मोदी की जंग बताकर।**
- प्र.मंत्री मोदी ने भी इस दबाव को स्वीकार किया और कहा कि हम पर दबाव बढ़ सकता है, हम उसे सहन करेंगे पर हम किसानों, पशुपालकों व लघु उद्योगों के हितों से समझौता नहीं करेंगे।**

चाहता है कि भारत कृषि बाज़ार को उसके उत्पादों के लिए खोले जो कि किसी भी सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि इसका मतलब होगा भारतीय किसानों की बर्बादी।

एक वरिष्ठ राजनयिक ने जब पूछा गया कि अमेरिका भारत के पीछे क्यों पड़ा है, तो उन्होंने कहा: ये सब अर्थव्यवस्था के कारण है।”

वाइट हाउस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को इस बात की पुष्टि भी कर दी कि “यह केवल रूसी तेल के बारे में नहीं है।”

बेसेंट ने कहा कि भारत ने व्यापार समझौता वार्ताओं में केवल “दिखावा” किया है।

नवरो ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “महान नेता” बताया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा, वह इस सिद्धांत

को मजबूत करता है कि वाशिंगटन की असली चिंता भारत की व्यापारिक बाधाएँ हैं।

नवरो ने कहा कि वे इस बात से हैरान हैं कि “भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है जहाँ बुद्धिमान लोग शासन कर रहे हैं, लेकिन वे हमसे आँखों में आँखें डालकर कहते हैं कि ‘हमारे टैरिफ दुनिया में सबसे ऊँचे नहीं हैं’, जबकि सच्चाई यह है कि वे सबसे ऊँचे हैं।”

भारत पर अमेरिकी दबाव का एक और पहलू है – ट्रम्प प्रशासन की एच वन-बी वीजा कार्यक्रम को लेकर नाराजगी, जिसका सबसे बड़ा लाभार्थी भारत है।

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड

लुटनिक ने बुधवार को कहा कि ट्रम्प प्रशासन एच वन-बी कार्यक्रम में बदलाव की योजना बना रहा है, जो

भारत ने ट्रंप की ‘‘टैरिफ ...

- पर, यह भी सच है कि, दीर्घकाल की दृष्टि से, भारत की यह सामना करने की नीति लाभकारी ही रहेगी, पर तत्कालिक रूप से आर्थिक पीड़ा जरूर होगी, क्योंकि भारत के अमेरिका को निर्यात होने वाले 45अरब डॉलर के माल पर भारी संकट आयेगा, कुछ रोजगार भी खत्म हो जायेंगे ।**

गति पर विवाद है, लेकिन यह सुधार अनुपालन को सरल बनाता है और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा दे सकता है। यह भारत के सुधार एजेंडे की निरंतरता को भी दर्शाता है, जिससे निवेशकों को यह परेसा मिलता है कि बाहरी उथल-पुथल से आंतरिक नीतिगत प्रगति बाधित नहीं होगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है- दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान। पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गोबा के नेतृत्व में दो उच्चस्तरीय समितियाँ नियामक छूट और संरचनात्मक सुधारों के खके तैयार कर रही हैं। साथ ही, प्रधानमंत्री

सलाह देती है यानि प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाहकार परिषद। यह दिखाता है कि भारत बाहरी झटकों के जवाब में दीर्घकालिक योजना और त्वरित आर्थिक सलाह दोनों को सक्रिय रूप से जुटा रहा है।

अल्पकाल में, टैरिफ वृद्धि से नुकसान होगा। श्रम-प्रधान क्षेत्रों के निर्यातकों को दबाव का सामना करना पड़ेगा, और वैकल्पिक बाजार विकसित होने से पहले व्यापार संतुलन बिगड़ सकता है। फिर भी, मोदी सरकार इस अस्थिरता को एक उल्टेपक्ष के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती है। घरेलू खेत पर दंव लगाकर, सुधारों में तेजी लाकर और वैश्विक सझेदारियों में विविधता लाकर, नई दिल्ली टैरिफ झटके को दीर्घकालिक लाभ में बदलने की रणनीति अपना रही है। हालाँकि इसका लाभ असमान रूप से मिलेगा। अल्पकालिक दर्द टालना संभव नहीं है। लेकिन दीर्घकालिक रूप से इसका लाभ एक अधिक मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था हो सकती है – जो वाशिंगटन को व्यापार नीति की अनिश्चितताओं से कम प्रभावित हो, और अपनी घरेलू मांग व विविध वैश्विक संबंधों पर अधिक आधारित हो।